अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	राजसमंद एवं सिरोही में 'फार्मर रजिस्ट्री आधारित उर्वरक वितरण प्रणाली' लागू
2.	'विधान सभा सदस्य - स्थानीय क्षेत्र विकास' (MLA-LAD) फंड में संशोधन
3.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट 2. राजस्थान में पहली बार 'मैकेनिकल लिटर पिकर मशीन' का उपयोग 3. 'खिलौना बैंक', 'प्रवेशोत्सव एवं पौधरोपण' कार्यक्रम 4. लेह-लद्दाख में आयोजित 'प्रथम सिंधु कुंभ' 5. 'लम्पी टीकाकरण अभियान' : ब्यावर से राज्य स्तरीय शुभारम्भ 6. नीलिमा अरोड़ा : माउंट एवरेस्ट फतह 7. पूर्वी प्रताप कच्छावा : ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक 8. अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन 4.0 : काठमांडू (नेपाल) 9. राजस्थान में 50 'डबल डेकर ई-बसों' का संचालन
4.	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (पीएमआरबीपी)
5.	खीर भवानी मेला
6.	निर्भय चेतना
7.	एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (एबीएस)
8.	फिनटेक सेक्टर का CRED-मेटा सौदा

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

राजस्थान परिदृश्य

राजसमंद एवं सिरोही में 'फार्मर रजिस्ट्री आधारित उर्वरक वितरण प्रणाली' लागू

चर्चा में क्यों?

- 25 जून, 2026 से राजस्थान कृषि विभाग द्वारा सिरोही एवं राजसमंद जिलों में 'फार्मर रजिस्ट्री आधारित उर्वरक वितरण प्रणाली' लागू करने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया।

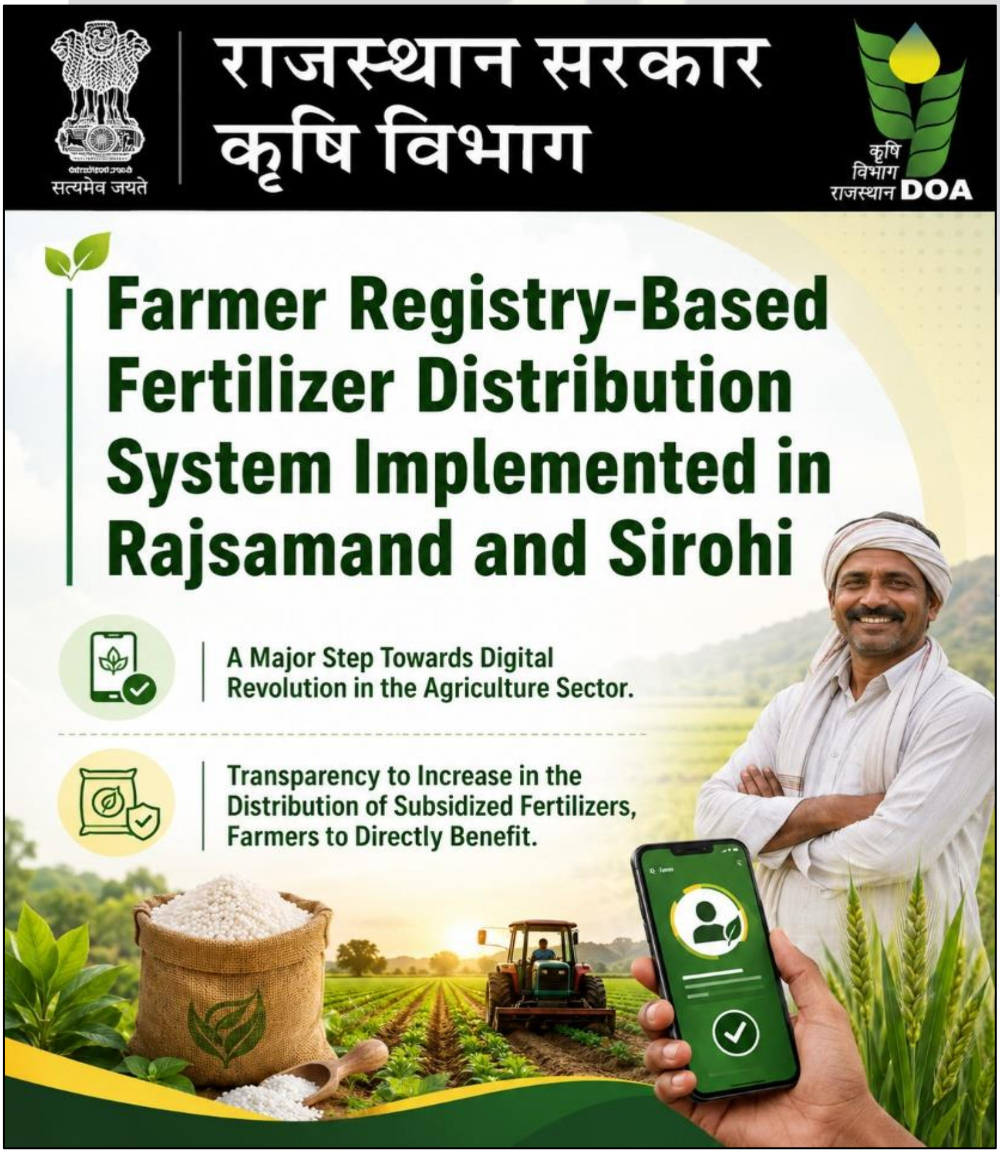

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

मुख्य बिन्दु:

- यह पायलट प्रोजेक्ट एग्रीस्टेक (AgriStack) योजना के अंतर्गत जारी फार्मर रजिस्ट्री का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय उर्वरक तंत्र के तहत शुरू किया गया है।
- ज्ञातव्य है कि कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता एवं सुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण तथा उर्वरक विभाग द्वारा फार्मर रजिस्ट्री और फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल्स (FFS) लागू किया जा रहा है।
- इस प्रणाली के माध्यम से किसानों को अनुदानित उर्वरकों का वितरण अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं डिजिटल माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
- फार्मर रजिस्ट्री आधारित FFS प्रणाली लागू होने से वास्तविक किसानों की पहचान सुनिश्चित होंगी तथा उर्वरकों के वितरण एवं उपयोग की निगरानी और अधिक सुदृढ़ हो सकेगी।
- इससे उर्वरकों की उपलब्धता, वितरण और स्टॉक प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

फार्मर रजिस्ट्री:

- फार्मर रजिस्ट्री एग्रीस्टेक प्रोजेक्ट की एक बुनियादी रजिस्ट्री है, जिसके अंतर्गत सभी किसानों को 11 डिजिट का यूनिक पहचान नंबर आवंटित किया जाता है।
- इसके लिए भू-अभिलेख के डेटाबेस को समेकित कर राजस्व ग्राम के प्रत्येक समान नाम वाले किसान व समान पिता के नाम वाले किसानों के ऑनलाइन बकेट (समस्त जानकारी एक साथ) तैयार कर मोबाइल ऐप, वेबसाइट द्वारा राज्य के सभी खसरों को शामिल करते हुए किसान के आधार से लिंक किया जाता है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

- **फार्मर रजिस्ट्री का उद्देश्य :** किसानों को सरकारी योजनाओं तक पहुँच की सुविधा मिल सके और शत-प्रतिशत लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित किया जा सके।
- **राजस्थान की स्थिति :** प्रदेश में जून, 2026 तक 86.66 लाख किसानों की फार्मर ID बनाई जा चुकी है। फार्मर ID बनाने में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

Q. 1 राजस्थान कृषि विभाग द्वारा जून 2026 में 'फार्मर रजिस्ट्री आधारित उर्वरक वितरण प्रणाली' का पायलट प्रोजेक्ट किन जिलों में शुरू किया गया?

A. जयपुर एवं जोधपुर
B. सिरोही एवं राजसमंद
C. कोटा एवं बूंदी
D. बीकानेर एवं बाड़मेर

Q. 2 'एग्रीस्टेक (AgriStack) प्रोजेक्ट' के अंतर्गत तैयार की जा रही 'फार्मर रजिस्ट्री' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसके तहत प्रत्येक किसान को 11 अंकों (digits) का एक यूनिक पहचान नंबर आवंटित किया जाता है।
2. इस व्यवस्था में किसानों की समस्त जानकारी को उनके आधार नंबर से लिंक किया जाता है।
3. जून 2026 तक राजस्थान में 85 लाख से अधिक किसानों की फार्मर ID बनाई जा चुकी है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

'विधान सभा सदस्य - स्थानीय क्षेत्र विकास' (MLA-LAD) फंड में संशोधन

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 'विधान सभा सदस्य - स्थानीय क्षेत्र विकास' (MLA-LAD) फंड से संबंधित नई गाइडलाइंस जारी की गई।

मुख्य बिन्दु:

- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 में राजस्थान विधानसभा की सदाचार समिति (Ethics Committee) ने 'विधान सभा सदस्य - स्थानीय क्षेत्र विकास' (MLA-LAD) फंड में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों में तीन विधायकों को नोटिस जारी किए थे।

नई गाइडलाइन:

1. कोई भी MLA विधायक निधि से विकास कार्यों की अनुशंसा तब ही कर पाएंगे, जब इसकी संबंधित पक्ष की ओर से स्पष्ट माँग रखी गई हो।
2. विधानसभा सदस्य केवल संबंधित कलेक्टर या जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ही अनुशंसा करेंगे। कार्यकारी एजेंसी का निर्धारण भी संबंधित कलेक्टर या जिला परिषद के CEO द्वारा ही किया जा सकेगा।
3. अनुशंसा प्राप्त होने के बाद संबंधित विभाग प्रस्तावित कार्य की व्यवहार्यता का परीक्षण करेगा। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करेगा कि उक्त कार्य सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत पहले से संचालित तो नहीं है।
4. विधायक को मिलने वाली ₹5 करोड़ की राशि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में किया जाना अनिवार्य होगा। यदि राशि शेष रहती है, तो उसे अगले वित्तीय वर्ष में कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, बल्कि वह लैप्स हो जाएगी।
5. नई गाइडलाइन के अनुसार अनुशंसा, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, कार्यकारी एजेंसी, वर्क ऑर्डर तथा कार्य की प्रगति से संबंधित सभी जानकारी पोर्टल पर लाइव अपडेट की जाएगी।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

- **राजस्थान विधानसभा की याचिका एवं सदाचार समिति के अध्यक्ष :** कैलाश वर्मा। (इसमें 12 सदस्य हैं)
- **कार्य :** 16वीं विधानसभा के लिए 2025-26 सत्र हेतु सदाचारिता और नैतिकता बनाए रखना।
- **राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च-स्तरीय जांच समिति**
- मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने विधायक निधि में भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु भास्कर सावंत की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया था।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

Q.1 हाल ही में जारी राजस्थान MLA-LAD फंड (विधायक निधि) की नई गाइडलाइंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. विधायक अपनी निधि से विकास कार्यों की अनुशंसा केवल तब ही कर पाएंगे जब संबंधित पक्ष की ओर से इसकी स्पष्ट मांग की गई हो।
2. विधायक को मिलने वाली ₹5 करोड़ की वार्षिक राशि यदि शेष रह जाती है, तो उसे अगले वित्तीय वर्ष में कैरी फॉरवर्ड (आगे स्थानांतरित) किया जा सकेगा।
3. विधायक निधि से संबंधित सभी जानकारी (जैसे प्रशासनिक स्वीकृति, वर्क ऑर्डर और प्रगति) को पोर्टल पर लाइव अपडेट किया जाएगा।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

CIVIL SERVICES

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

न्यूज़ इन शॉर्ट्स

क्र. सं.	न्यूज़
1.	**राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट** ■ हाल ही में, राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (RWSLIP) के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य-स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ■ **आयोजन स्थल :** स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट (SIAM), दुर्गापुरा, जयपुर। ■ राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (RWSLIP) का उद्देश्य जल उपयोग क्षमता में सुधार और कृषि उत्पादकता को बढ़ाकर किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना है। ■ **वित्त पोषण :** जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) द्वारा।
2.	**राजस्थान में पहली बार 'मैकेनिकल लिटर पिकर मशीन' का उपयोग** ■ राजस्थान में पहली बार अत्याधुनिक 'मैकेनिकल लिटर पिकर मशीन' का उपयोग जयपुर को साफ-सुथरा और सुंदर बनाने के लिए शुरू किया गया है। ■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगानेर, जयपुर में आयोजित एक समारोह के दौरान इन हाई-टेक मशीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ■ ये अत्याधुनिक मैकेनिकल लिटर पिकर मशीनें फुटपाथों, संकरी गलियों और ट्रांसफार्मर के नीचे से भी प्रभावी ढंग से कचरा उठाने में सक्षम है।
3.	**'खिलौना बैंक', 'प्रवेशोत्सव एवं पौधरोपण' कार्यक्रम** ■ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश के आँगनबाड़ी केंद्रों पर 3-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के सर्वांगीण विकास और नामांकन बढ़ाने के लिए 24 जून से 1 जुलाई, 2026 तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ■ इस अभियान के तहत 'खिलौना बैंक' की स्थापना, 'प्रवेशोत्सव' और 'पौधारोपण' कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

4.	**लेह-लद्दाख में आयोजित 'प्रथम सिंधु कुंभ'** ■ लेह-लद्दाख के ऐतिहासिक सिंधु घाट पर हाल ही में 'प्रथम सिंधु कुंभ' का आयोजन किया गया। ■ इस कुम्भ में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हिस्सा लिया।
5.	**'लम्पी टीकाकरण अभियान' : ब्यावर से राज्य स्तरीय शुभारम्भ** ■ 24 जून, 2026 को पशुपालन, डेयरी एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने ब्यावार से गोवंश को लम्पी स्किन डिजीज (LSD) से सुरक्षित रखने हेतु राज्य स्तरीय टीकाकरण अभियान का शुभारम्भ किया। ■ **चरण :** दूसरा। ■ राज्य में वर्ष 2025-26 के दौरान 108.95 लाख गोवंशीय पशुओं का टीकाकरण किया गया था। वर्ष 2026-27 के लिए 111.51 लाख पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
6.	**नीलिमा अरोड़ा : माउंट एवरेस्ट फतह** ■ जयपुर की नीलिमा अरोड़ा ने थैलेसीमिया माइनर के बावजूद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट (8,849 मीटर) फतह कर इतिहास रचा। ■ वह थैलेसीमिया माइनर से ग्रसित होकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला हैं।
7.	**पूर्वी प्रताप कच्छावा : ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक** ■ जयपुर निवासी निशानेबाज पूर्वी प्रताप कच्छावा ने जर्मनी के सुहल में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में '25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल महिला टीम स्पर्धा' में स्वर्ण पदक जीता। ■ पूर्वी 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक भी हैं।
8.	**अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन 4.0 : काठमांडू (नेपाल)** ■ काठमांडू (नेपाल) में आयोजित अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन 4.0 में राजस्थान के तीन डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया। ■ **सम्मानित व्यक्तित्व :** डॉ. स्वरूपानन्द सरकार, डॉ. टी. पी. तिवारी, डॉ. आरती पुरोहित। ■ **आयोजन :** 12 से 14 जून, 2026 तक।

9.	राजस्थान में 50 'डबल डेकर ई-बसों' का संचालन
	■ राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 50 'डबल डेकर ई-बसें' चलाने की घोषणा की गई है। ■ ये 50 वातानुकूलित डबल डेकर बसें विशेष रूप से पर्यटकों के लिए चलाई जाएंगी। ये प्रमुख पर्यटन शहरों जैसे जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के ऐतिहासिक स्थलों को आपस में जोड़ेंगी।

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

Q.1 राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (RWSLIP) मुख्य रूप से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा वित्त पोषित है?

A. विश्व बैंक
B. जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी
C. न्यू डेवलपमेंट बैंक
D. एशियाई विकास बैंक

Q. 2 राजस्थान में राज्य स्तरीय 'लम्पी टीकाकरण अभियान' के दूसरे चरण का शुभारम्भ कहाँ से किया गया?

A. जयपुर
B. ब्यावर
C. जोधपुर
D. बीकानेर

Q.3 राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण हेतु कुल कितनी 'डबल डेकर ई-बसों' के संचालन की योजना को मंजूरी दी गई है?

A. 50
B. 25
C. 100
D. 75

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

राष्ट्रीय परिदृश्य

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (पीएमआरबीपी)

चर्चा में क्यों?

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं।

मुख्य बिन्दु:

- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत के राष्ट्रपति द्वारा वीर बाल दिवस (26 दिसंबर) पर प्रदान किया जाता है।
- 2019 में अपने वर्तमान स्वरूप में स्थापित यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को छह श्रेणियों में असाधारण उपलब्धियों के लिए सम्मानित करता है: वीरता, कला और संस्कृति, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल।
- पात्र होने के लिए, नामांकित व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
  - भारत में रहने वाला भारतीय नागरिक होना चाहिए
  - इससे पहले यह पुरस्कार प्राप्त नहीं किया हो
  - नामांकन की अंतिम तिथि से पहले के दो वर्षों के भीतर मान्यता प्राप्त उपलब्धि हासिल कर ली हो ।
- हालांकि यह पुरस्कार आम तौर पर मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाता है, लेकिन असाधारण मामलों पर विचार किया जा सकता है।
- यह पुरस्कार भारत में बच्चों के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

इतिहास एवं संस्कृति

खीर भवानी मेला

चर्चा में क्यों?

- कश्मीर घाटी में, ज्येष्ठ अष्टमी के अवसर पर वार्षिक मेला खीर भवानी को धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है।

मुख्य बिन्दु:

- यह कश्मीरी पंडित समुदाय के सबसे महत्त्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जिसके दौरान भक्त माता रागन्या देवी को खीर, दूध, फूल और सुगंधित पत्ते अर्पित करते हैं।

खीर भवानी मंदिर

- यह देवी रागन्या देवी को समर्पित है, जिन्हें देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है।
- मूल मंदिर का निर्माण महाराजा प्रताप सिंह द्वारा लगभग 1912 में जम्मू और कश्मीर के गांदरबल में कराया गया था। बाद में महाराजा हरि सिंह ने इसका सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार करवाया।
- मंदिर की एक विशिष्ट विशेषता इसके केंद्र में स्थित एक षट्भुजाकार झरना है, जिसे इसके पवित्र जल के लिए पूजा जाता है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

योजनाएँ एवं नीतियाँ

निर्भय चेतना

चर्चा में क्यों?

- पंचायती राज मंत्रालय ने निर्भय चेतना पर तीन दिवसीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम का आयोजन किया।

मुख्य बिन्दु:

- निर्भय चेतना , पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, 2026 में शुरू की गई निर्भय रहो पहल के तहत एक महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप है ।

इसमें तीन पूरक घटक शामिल हैं :

- निर्भय नेत्री निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के बीच क्षमता निर्माण और कानूनी जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करती हैं;
- निर्भय चेतना का उद्देश्य निर्वाचित पुरुष प्रतिनिधियों को लैंगिक समानता और महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाना है; और
- निर्भय दृष्टि योजना के तहत पंचायतों में प्रौद्योगिकी-आधारित सुरक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए रणनीतिक ग्रामीण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की परिकल्पना की गई है।

Q. 'निर्भय चेतना' पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है?

A. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

B. ग्रामीण विकास मंत्रालय

C. पंचायती राज मंत्रालय

D. गृह मंत्रालय

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (एबीएस)

चर्चा में क्यों?

- भारत के जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत पहुँच और लाभ साझाकरण (एबीएस) ढाँचे ने 2008 से अब तक 266 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाई है, जिसमें से लगभग 145 करोड़ रुपये लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं।

मुख्य बिन्दु:

एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (एबीएस) क्या है?

- एबीएस से तात्पर्य उस ढाँचे से है जिसके माध्यम से जैविक संसाधनों और उनसे जुड़े पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों को उन समुदायों के साथ निष्पक्ष और समान रूप से साझा किया जाता है जिन्होंने इन संसाधनों का संरक्षण किया है।
- यह जैविक विविधता पर सम्मेलन (सीबीडी) के अंतर्गत एक सिद्धांत है ।
- भारत जैविक विविधता अधिनियम, 2002 और इसके हालिया संशोधन जैविक विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से जैविक विविधता को कार्यान्वित करता है।

महत्त्व

- भारत का एबीएस ढाँचा नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को आगे बढ़ा रहा है, राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना 2024-2030 का समर्थन कर रहा है, और कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाँचे में योगदान दे रहा है।

जैविक विविधता अधिनियम, 2002

- यह अधिनियम संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता सम्मेलन (सीबीडी), 1992 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पेश किया गया था ।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

- यह जैविक संसाधनों तक पहुँच और ऐसे उपयोग और पहुँच से उत्पन्न होने वाले लाभों को साझा करने के लिए एक ढाँचा प्रदान करता है। यह पहुँच और लाभ साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल के अनुरूप है।

नागोया प्रोटोकॉल

- आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के निष्पक्ष और समान बंटवारे पर नागोया प्रोटोकॉल (एबीएस) जैविक विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) का एक पूरक समझौता है।
- इसे 2010 में जापान के नागोया में अपनाया गया था और यह 2014 में लागू हुआ।

Q. "जैविक संसाधनों का संरक्षण केवल वैज्ञानिक प्रयास नहीं, बल्कि समुदायों के प्रति सामाजिक न्याय का विषय भी है।" इस कथन के आलोक में भारत के ABS ढाँचे और उसके महत्त्व का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

विज्ञान प्रौद्योगिकी

फिनटेक सेक्टर का CRED-मेटा सौदा

चर्चा में क्यों?

- भारत के प्रख्यात फिनटेक उद्यमी कुणाल शाह को व्हाट्सएप का वैश्विक सीईओ नियुक्त किया गया है।

मुख्य बिन्दु:

- मेटा कंपनी क्रेड में 900 मिलियन डॉलर का निवेश भी कर रही है, जिससे भारत के फिनटेक क्षेत्र और भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा उत्पन्न डेटा पर अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों के बढ़ते नियंत्रण को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।
- मेटा-क्रेड का यह लेनदेन ऐसे समय में हुआ है, जब भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र पर अमेरिकी कंपनियों से जुड़े प्लेटफार्मों का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है।
- PhonePe में Walmart का लगभग 72% हिस्सा है, Google के पास Google Pay का स्वामित्व है और Meta के पास WhatsApp Pay का स्वामित्व है।
- प्रस्तावित क्रेड निवेश भारतीय सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढाँचे पर आधारित क्षेत्र में विदेशी प्रौद्योगिकी दिग्गजों के नियंत्रण को और मजबूत करेगा।
- कई भारतीय फिनटेक स्टार्टअप दीर्घकालिक भारतीय स्वामित्व वाली डिजिटल चैंपियन कंपनियाँ बनाने की तुलना में अंततः विदेशी खरीदारों को बेचने के लिए कंपनियां बनाने में अधिक रुचि रखते प्रतीत होते हैं।

फिनटेक क्या है?

- भारत में फिनटेक क्षेत्र से तात्पर्य वित्तीय सेवाओं को बेहतर बनाने, उनमें नवाचार लाने और उन्हें सुव्यवस्थित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग से है।
- इस क्षेत्र में डिजिटल भुगतान, ऋण, बीमा, धन प्रबंधन और व्यक्तिगत वित्त सहित वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जो सभी प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित हैं।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

भारत में फिनटेक क्षेत्र

- भारतीय फिनटेक उद्योग का अनुमान है कि 2024 में यह लगभग 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होगा और 2029 तक लगभग 420 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है ।
- भारत में फिनटेक कंपनियों की संख्या के मामले में वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान है और डिजिटल भुगतान की मात्रा के मामले में यह वैश्विक स्तर पर अग्रणी है।
- 2016 में महज 1 मिलियन लेनदेन से शुरू होकर, यूपीआई ने तब से 10 बिलियन लेनदेन का ऐतिहासिक आँकड़ा पार कर लिया है।
- **भारत में फिनटेक क्षेत्र के लिए सरकारी पहल**
  - प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई
  - इंडिया स्टैक
  - आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस)
  - सेंट्रल केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें)
  - यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई)
  - भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस)
  - फिनटेक के लिए स्व-नियामक संगठन (एसआरओ)
  - राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एनडीएचएम) और संबंधित पहलें
- **रेगुलेटरी सैंडबॉक्स:** इसे भारतीय रिजर्व बैंक और बाद में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया था।
  - यह फिनटेक कंपनियों को पूर्ण पैमाने पर तैनाती से पहले एक नियंत्रित नियामक वातावरण में अभिनव उत्पादों का परीक्षण करने की अनुमति देता है।
- **IFSC, GIFT सिटी में फिनटेक हब:** भारत को वैश्विक फिनटेक लीडर के रूप में बढ़ावा देने के लिए गुजरात के गाँधीनगर में एक विश्व स्तरीय फिनटेक हब विकसित किया गया है।

Q. 'डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर' (DPI) क्या है? फिनटेक के संदर्भ में भारत की प्रगति में इसकी क्या भूमिका है?